हिमाचल में खुलेंगे कॉमन सर्विस सेंटर

सूचना प्रौद्योगिकी सचिव ने डीसी को दिए आदेश, जल्द निपटाएं कार्य

- आमजन को सभी विभागों के फार्म एक ही स्थान पर मिलेंगे
- बाबुओं की हेकड़ी पर भी लगेगी लगाम
- दिल्ली की फर्म के साथ हुआ समझौता

मस्तराम डलैत

धर्मशाला — प्रदेश के पंचायत सचिवों और पटवारियों की हेकड़ी खत्म हो जाएगी और सरकारी दफ्तर के बाबू भी आम जनमानस पर रौब नहीं जमा सकेंगे। इन सभी की दादागिरी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने प्रदेश में कामन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे इन सेंटरों में आम लोगों की हर जरूरत पूरी होगी। मसलन सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, राजस्व रिकार्ड तथा बिजली, पानी और फोन संबंधित तमाम फार्म उक्त सेंटरों पर उपलब्ध होंगे, जिनके लिए लोगों को कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अरविंद मेहता ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर इस योजना में जुट जाने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए जा रहे कामन सर्विस सेंटरों के लिए राज्य सरकार और दिल्ली की जूम डिवेलपर कंपनी के बीच समझौता हुआ है।

लिहाजा सचिव सूचना प्रौद्योगिकी ने उपायुक्तों को भेजे अपने पत्र में कहा है कि उक्त कंपनी से मिलकर कार्य तुरंत आरंभ किया जाए। सूत्रों का कहना है कि जूम डिवेलपर कंपनी देश के नौ प्रदेशों में सक्रिय है और इसके चलते हिमाचल सरकार ने उसके साथ समझौता किया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने उक्त कंपनी को सभी विभागों का रिकार्ड उपलब्ध करवाया और कंपनी इसे अपने साफ्टवेयर में डाउन लोड कर लेगी। डाटा बेस के आधार पर उक्त सेंटरों में आम लोगों को हर प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा।

इसके लिए कामन सर्विस सेंटर का भी निर्माण होगा। पता चला है कि उक्त सेंटरों से सबसे ज्यादा लाभ पंचायत सचिव और पटवारियों के चक्कर काटने वाले लोगों को होगा। इसके अलावा जिला मुख्यालय और प्रदेश मुख्यालय में उपलब्ध होने वाले फार्म भी इन सेंटरों में आसानी से मिल जाएंगे।

''सरकार से ऐसे आदेश प्राप्त हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कामन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। जूम डिवेलपर कंपनी और प्रशासन मिलकर इन सेंटरों को स्थापित करेंगे''

[illegible]

एडीसी कांगड़ा